एक्ज़िम बैंक EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस
निर्यात लाभ

सितंबर 2019
खंड XXXV अंक III

इस अंक में

1 भारत के सेवा क्षेत्र में व्यापार प्रतिबंध
3 सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन के नव उपाय
4 दुनियाभर में बढ़ी सोने की चमक
6 बढ़ता व्यापार संरक्षणवाद: भारत पर असर
7 उदारीकरण, वेतन और क्षेत्रवार वृद्धि: भारत के संबंध सामान्य संतुलन विश्लेषण
8 एक्ज़िम बैंक का ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) कार्यक्रम
9 एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं
10 तिमाही गतिविधियां
11 एक्ज़िमिअस शिक्षण केंद्र की गतिविधियां
12 एक्ज़िम बाज़ार के जरिए स्थानीय दस्तकारों को एक्ज़िम बैंक का सहयोग
13 चुनिंदा देशों का आर्थिक परिदृश्य
14 मुद्रा की प्रवृत्तियां
15 आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था
16 व्यापार और भागीदारी अवसर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

प्रधान कार्यालय :
केंद्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400 005
Tel.: 022 2217 2600
Email : ccg@eximbankindia.in

भारत के सेवा क्षेत्र में व्यापार प्रतिबंध

भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत के सेवा क्षेत्र का अहम योगदान है। सकल मूल्य योजन (जीवीए) में 50% से अधिक का हिस्सा सेवा क्षेत्र का ही है। इसके अतिरिक्त, 2018 में भारत से कुल निर्यातों में भारत के सेवा निर्यातों का हिस्सा 38% रहा।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के आपूर्ति माध्यमों के आधार पर सेवा व्यापार के आंकड़ों (टिसमॉस) के अनुसार, 2005-2017 के दौरान सेवाओं के वैश्विक निर्यात का लगभग 50% मोड 3 श्रेणी में रहा, जिसमें विदेश में 'वाणिज्यिक उपस्थिति की शुरुआत' और इसके बाद मोड 1 शामिल है। भारत के मामले में, मोड 1 श्रेणी में सेवाओं का निर्यात 70% से अधिक है , जो निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बॉडी शॉपिंग सहित फोन, फैक्स अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रदान की गई सेवाएं हैं।

तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र से मिली इस बढ़त के बावजूद इस क्षेत्र में सुधार की काफी गुंजाइश है। भारतीय सेवा बाजार में अब भी विदेशी निवेशकों के लिए खुलेपन का अभाव है।

भारतीय सेवा व्यापार नीति में बाधाओं का तुलनात्मक अध्ययन ओईसीडी द्वारा विकसित सेवा व्यापार प्रतिबंधात्मकता सूचकांक (एसटीआरआई) का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है। भारत के लिए यह सूचकांक दिखाता है कि लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापार बधाओं में बड़ा अंतर है। इस सूचकांक में भारत का स्कोर बेहतर है है। नियामकीय फ्रेमवर्क इसकी बड़ी वजह है, जो पूंजी और व्यक्तियों के प्रवाह का नियमन करता है। हालांकि सेवाओं के अंतर्गत हॉरिजेंटल और क्षेत्र विशिष्ट प्रतिबंध हो सकते हैं, लेकिन एसटीआरआई के अंतर्गत कुछ हॉरिजेंटल उपाय हैं, जो सभी क्षेत्रों के लिए लागू हो सकते हैं। परिणामस्वरूप, क्षेत्र विशिष्ट उपाय के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में कम बाधाएं हैं तो हॉरिजेंटल उपाय पूरे क्षेत्र में बधाएं उत्पन्न कर देते हैं। हॉरिजेंटल बाधाओं को संक्षिप्त रूप में पांच नीतिगत क्षेत्रों के अंतर्गत समझा जा सकता है:

- **विदेशी निवेश पर प्रतिबंध**

  इस श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख बाधा विदेशी निवेश के क्षेत्र में है। इनमें अधिकतम विदेशी इक्विटी शेयर से संबंधित बाधाएं; विदेशी विलय और अधिग्रहण; सार्वजनिक नियंत्रण वाली फर्मों में विदेशी निवेशकों द्वारा अधिग्रहीत किए जा सकने वाले शेयरों की निर्धारित सीमा; पूँजी और निवेश के अंतरण संबंधी शर्तें; विदेशी व्यक्तियों द्वारा भूमि और रियल एस्टेट का अधिग्रहण और उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध; विदेशी निवेशकों द्वारा रखे जाने वाले शेयरों अथवा बॉन्डों के प्रकार संबंधी प्रतिबंध शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आवासीय जरूरतों, विनियमों और डाटा की लोकेशन तथा अंतरण संबंधी बाधाएं भी हो सकती हैं।

- **विधिक रूप से मान्य व्यक्तियों (नैचुरल पर्सन्स) की आवाजाही पर रोक**

  भारत के अधिकतर क्षेत्रों में मुख्य रूप से दो स्थितियां हैं - श्रम बाजार परीक्षण और रहने की अवधि की सीमाएं। कुछ अन्य स्थितियां कानूनों और विनियमों से जुड़ी होती हैं, जो विदेशों में प्राप्त शिक्षा को मान्यता देने की प्रक्रिया से संबंधित होती हैं। वस्तुतः भारत ने अल्प विकसित देशों के लिए अपनी वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने की पहल की है और डब्ल्यूटीओ में इसे अधिसूचित भी किया है। वीजा फीस में छूट देने वाला भारत इकलौता सदस्य देश है।

- **प्रतिस्पर्धा के लिए बाधाएं**

  नीतिगत उपाय के बारे में कि नियामक निकाय द्वारा निर्णयों की अपील की जा सकती है, इस बारे में विदेशियों के खिलाफ कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, किसी बाजार में जब व्यवसाय पद्धतियां प्रतिस्पर्धा में बाधा बनती हैं तो उनसे निपटने की व्यवस्था के संबंध में कोई भी व्यक्ति प्रतिस्पर्धा आयोग में गैर-प्रतिस्पर्धी पद्धतियों की जांच करने के लिए अनुरोध कर सकता है और प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णय को प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण में

चुनौती दी जा सकती है। कुछ अन्य बाधाओं में न्यूनतम पूँजी जरूरतें, क्षेत्र में कम से कम एक प्रमुख फर्म पर सरकारी नियंत्रण और विज्ञापनों पर प्रतिबंध शामिल हैं।

- **विनियामकीय पारदर्शिता**

  नीतिगत उपाय के संबंध में विनियामकों की जानकारी उनके लागू होने से पहले उचित समय पर आम जन तक पहुंचाना कानूनी बाध्यता है। संसद के अधिनियम गजट में प्रकाशित किए जाते हैं, किन्तु इनके प्रकाशन और लागू होने की अवधि के बीच कोई न्यूनतम सांविधिक समयावधि नहीं दी गई है। अन्य बाधाओं में व्यवसाय सुगमता संबंधी मसले शामिल हैं। जैसे, वीजा प्रक्रिया में लगने वाला समय, बिजनेस वीजा प्राप्त करने में आने वाली लागत, कोई कंपनी रजिस्टर कराने के लिए तमाम जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने में लगने वाले दिन आदि।

- **अन्य पक्षपाती उपाय**

  केंद्र सरकार एक अधिसूचना के जरिए बोलीकर्ताओं की किसी भी श्रेणी से किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की अनिवार्य खरीद का प्रावधान कर सकती है अथवा स्थानीय स्तर पर विनिर्मित वस्तुओं या स्थानीय सेवा प्रदाताओं को बढ़ावा देने को आधार बनाकर बोलीकर्ताओं को प्राथमिकता दे सकती है।

चुनिंदा देशों के लिए सेवा व्यापार प्रतिबंधात्मकता सूचकांक, 2018

क्षेत्र	ऑस्ट्रेलिया	चिली	जापान	तुर्की	यूके	यूएसए	ब्राजील	चीन	भारत	इंडोनेशिया	रूस	द. अफ्रीका
लेखा	0.183	0.096	0.196	1.000	0.270	0.169	0.303	0.754	0.827	0.708	0.325	0.270
हवाई परिवहन	0.305	0.165	0.395	0.554	0.393	0.534	0.560	0.479	0.573	0.481	0.571	0.464
वास्तुकला	0.150	0.146	0.148	0.268	0.186	0.204	0.283	0.233	0.684	0.312	0.310	0.235
प्रसारण	0.189	0.294	0.258	0.404	0.171	0.266	0.480	0.707	0.439	0.432	0.433	0.423
वाणिज्य बैंकिंग	0.172	0.214	0.201	0.227	0.172	0.206	0.443	0.409	0.517	0.489	0.354	0.336
कंप्यूटर	0.161	0.170	0.163	0.278	0.178	0.203	0.293	0.342	0.377	0.334	0.377	0.227
निर्माण	0.192	0.163	0.123	0.250	0.145	0.251	0.247	0.341	0.366	0.441	0.365	0.241
कुरियर	0.369	0.493	0.262	0.472	0.171	0.378	0.545	0.881	0.570	0.469	0.405	0.490
वितरण	0.137	0.140	0.125	0.168	0.116	0.163	0.220	0.265	0.445	0.649	0.263	0.223
इंजीनियरिंग	0.132	0.160	0.118	0.239	0.152	0.221	0.258	0.254	0.303	0.301	0.320	0.245
बीमा	0.195	0.168	0.166	0.219	0.148	0.288	0.368	0.444	0.565	0.486	0.390	0.198
विधिक	0.131	0.161	0.538	0.610	0.182	0.206	0.309	0.532	0.886	0.890	0.251	0.310
लॉजिस्टिक्स कार्गो हैंडलिंग	0.218	0.247	0.210	0.360	0.160	0.248	0.351	0.412	0.404	0.463	1.000	0.368
लॉजिस्टिक्स कस्टम्स ब्रोकरेज	0.166	0.351	0.160	0.282	0.148	0.237	0.284	0.336	0.328	0.314	0.375	0.278
लॉजिस्टिक्स ढुलाई भाड़ा	0.168	0.201	0.201	0.281	0.136	0.222	0.256	0.340	0.316	0.380	0.337	0.281
लॉजिस्टिक्स भंडारण और भंडारगृह	0.168	0.199	0.173	0.306	0.162	0.220	0.320	0.361	0.400	0.391	1.000	0.290
समुद्री परिवहन	0.184	0.204	0.191	0.243	0.201	0.369	0.313	0.358	0.395	0.557	0.436	0.272
मोशन पिक्चर्स	0.151	0.185	0.103	0.226	0.179	0.155	0.294	0.615	0.319	0.328	0.343	0.220
रेल ढुलाई परिवहन	0.145	0.234	0.198	0.245	0.168	0.164	0.262	0.298	1.000	0.357	0.994	0.314
सड़क ढुलाई परिवहन	0.133	0.127	0.124	0.206	0.167	0.188	0.230	0.273	0.315	0.467	0.294	0.173
साउंड रिकॉर्डिंग	0.143	0.188	0.106	0.237	0.155	0.178	0.222	0.498	0.280	0.233	0.303	0.218
टेलीकॉम	0.173	0.235	0.253	0.211	0.171	0.172	0.267	0.682	0.421	0.644	0.381	0.306

स्रोत: ओईसीडी

चुनिंदा देशों में सबसे कम एसटीआरआई चुनिंदा देशों में उच्चतम एसटीआरआई

आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते वैश्विक मांग में आई कमी के बीच भारत के निर्यातों में वृद्धि की रफ्तार हाल के समय में कुछ धीमी पड़ गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले पांच महीनों में भारतीय निर्यातों में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। भारत सरकार निर्यातों में वृद्धि के लिए प्रयासरत है और 2024-25 तक सरकार ने भारत से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के निर्यातों का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने निर्यातों को बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यातकों की स्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए हैं।

- **निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट के लिए नई योजना**

  इस योजना का उद्देश्य निर्यातों में शुल्क के रूप में लगने वाली निर्यातकों की लागत की भरपाई करना है। साथ ही यह योजना 1 जनवरी, 2020 से भारत से वस्तु निर्यात योजना की जगह लागू हो जाएगी। इस योजना के जरिए निर्यातों में लगने वाले तमाम शुल्क और लेवी माफ हो जाएंगे और इससे लगभग 50,000 करोड़ रुपये का भार आने की संभावना है।

- **अदत्त इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी मसले का समाधान**

  सरकार ने निर्यातकों के लिए त्वरित और ऑटोमैटिक रिफंड हेतु इलेक्ट्रॉनिक रिफंड मॉडल की घोषणा की है। इस मॉडल से मौजूदा रुकी हुई निधियों की निगरानी करने और उन्हें कम करने तथा निर्यातकों को जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के त्वरित रिफंड में मदद मिलेगी।

- **निर्यातकों को कार्यशील पूँजी ऋण देने वाले बैंकों को उच्चतर बीमा कवर**

  निर्यातकों को कार्यशील पूँजी ऋणों के लिए ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा बैंकों को उच्चतर बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इससे सरकार पर प्रतिवर्ष 1700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। तदनुसार, निर्यात ऋण के लिए ब्याज दरें भी कम रहने की उम्मीद है। रुपया राशि के ऋणों के लिए ब्याज दर 8 प्रतिशत से कम और विदेशी मुद्रा विनियम ऋण के लिए 4 प्रतिशत से कम रहने की उम्मीद है। ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा उच्चतर कवर से निर्यातों की लागत में कमी आएगी और यह योजना विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए लाभदायक होगी।

- **निर्यात ऋण के लिए संशोधित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) मानदंड**

  निर्यात ऋण के लिए संशोधित पीएसएल मानदंडों के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्यातकों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के अंतर्गत 36,000 करोड़ से 68,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि निर्यात ऋण के रूप में जारी की जाएगी।

- **निर्यात वित्त डाटा की प्रभावी निगरानी**

  वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक अंतर-मंत्रालयी कार्यकारी समूह द्वारा निर्यात वित्त संबंधी डाटा की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। यह समूह निर्यात वित्त के संवितरण को एक सार्वजनिक डैशबोर्ड के जरिए ट्रैक करेगा और व्यापार संस्थानों के सहयोग से इस डाटा की समीक्षा भी की जाएगी।

- **हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर तमाम प्रक्रियाओं और निर्यात में लगने वाले समय को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना**

  सीमा शुल्क संबंधी महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाएं, जिनके लिए मैनुअल प्रक्रिया जरूरी होती है, सहित निर्यात लॉजिस्टिक्स से संबंधित सभी मंजूरियां डिजिटल की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बंदरगाह और हवाई अड्डे पर प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को रियल टाइम में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि उनमें सुधार लाया जा सके।

- **वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल**

  भारतीय निर्यातों को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार चार शहरों में मेले आयोजित कराएगी। इन मेलों में रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, योग, पर्टयन, टेक्सटाइल्स और लेदर जैसे क्षेत्रों पर फोकस रखा जाएगा। इससे विशेष रूप से हस्तशिल्पों में छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा और बेहतर व्यापार के सूत्र बनेंगे।

- **ई-कॉमर्स बाजार के लिए हस्तशिल्प उत्पादों का संवर्धन**

  ई-कॉमर्स बाजार तक हस्तशिल्प उद्योग की पहुंच को आसान बनाने और इस उद्योग में लगे शिल्पकारों को डिजिटल युग के लिए तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर एक कार्यक्रम में नामित करने की योजना है।

- **मुक्त व्यापार करार (एफटीए) उपयोगिता मिशन शुरू करना**

  भारत द्वारा हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार करारों में वर्तमान में उपलब्ध रियायती टैरिफ के बेहतर प्रयोग के लिए एक एफटीए उपयोगिता मिशन की परिकल्पना की गई है। यह मिशन विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों में रियायती टैरिफ के बेहतर इस्तेमाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्यात गृहों, भारतीय निर्यात संगठन संघ और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत 32 निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ मिलकर काम करेगा।

- **मूल स्थान प्रबंधन तंत्र (ओएमएस) की शुरुआत**

  निर्यातकों को उत्पत्ति (मूल) स्थान संबंधी प्रमाण पत्र हासिल करने में मदद करने और व्यवसाय सुगमता में सुधार लाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा ओएमस की शुरुआत की जाएगी।

- **अनिवार्य तकनीकी मानकों को समयबद्ध तरीके से अपनाना**

  अनिवार्य तकनीकी मानकों को समयबद्ध तरीके से अपनाने से निम्न स्तरीय आयातों को रोकने और भारत के अपने निर्यातों की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में एक नये कार्यकारी समूह की घोषणा की गई है, जो बेहतर मानकों को अपनाने के संबंध में समयसीमा का खाका खींचेगा।

- **परीक्षण और प्रमाणन के लिए किफायती बुनियादी ढांचा**

  परीक्षण और प्रमाणन के लिए किफायती बुनियादी ढांचागत सुविधाएं पीपीपी मॉडल के आधार पर विकसित की जाएंगी और उनका विस्तार किया जाएगा, ताकि निर्यातक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत तमाम परीक्षण और प्रमाणन भारत में ही कर सकें।

4 दुनियाभर में बढ़ी सोने की चमक

हालिया घटनाक्रम

हाल में सोने की कीमतों में दुनियाभर में बढ़ोत्तरी देखी गई। इसकी कीमतें 7 अगस्त, 2019 को 1500 यूएस डॉलर प्रति आउंस को पार कर गईं और 4 सितंबर, 2019 को बढ़कर 1551 यूएस डॉलर प्रति आउंस हो गईं। यह पिछले पांच वर्षों में सोने का उच्चतम भाव है। अप्रैल–जून 2018 से अप्रैल–जून 2019[1] के दौरान सोने की मांग में वर्ष–दर–वर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारत में वायदा बाजार में सोने की कीमतें वर्ष के प्रारंभ में 31,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास थीं, जो आठ महीने में 23 प्रतिशत बढ़कर लगभग 39,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गईं। हाजिर बाजार (स्पॉट मार्केट) में सोने की कीमतें 40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम[2] तक पहुंच गईं। अप्रैल–जून 2018 के दौरान भारत में सोने की मांग 189.2 टन थी, जो अप्रैल–जून 2019 में 13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के साथ 213.2 टन हो गई। वस्तुओं की मांग बढ़ने से उनके दाम बढ़ने के आसार भी बढ़ जाते हैं।

भारत 2018–19 में 32.8 बिलियन यूएस डॉलर के आयातों के साथ सोने का तीसरा सबसे बड़ा आयातक रहा। दुनिया के कुल स्वर्ण आयातों में 11.1 प्रतिशत हिस्सा अकेले भारत का ही रहा। भारत के लिए सोने का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता स्विट्जरलैंड रहा, जिसने भारत द्वारा कुल स्वर्ण आयातों के 46.2 प्रतिशत की आपूर्ति की। भारत ने 2018 के दौरान 12.4 बिलियन यूएस डॉलर के आभूषणों का निर्यात किया। सोने की मांग में यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से इक्विटी से सोने में निवेश बढ़ने के कारण रही। वैश्विक मंदी के चलते निवेश भी सोने जैसे सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। अप्रैल–जून 2019 में सोने में कुल निवेश मांग 44.5 टन (13,040 करोड़ रुपये) की रही, जिसमें अप्रैल–जून 2018 की 39.3 टन की मांग की तुलना में 13 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। मूल्य के लिहाज से देखें तो यह 2018 की दूसरी तिमाही में 11,060 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019 की दूसरी तिमाही में 13,040 करोड़ रुपये की हो गई। मांग में बढ़ोत्तरी के चलते सोने की कीमतों में भी उछाल आया है।[3]

बुरे वक्त में सोने में लगाए गए पैसे को परंपरागत रूप से सुरक्षित माना जाता है। प्रतिकूल मौद्रिक नीति परिदृश्य में ब्याज दर में गिरावट बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट लाती है। इसलिए सोने जैसे गैर–यील्ड वाले निवेश आकर्षक बन पड़ते हैं। प्रमुख

सोने की वैश्विक कीमतें (यूएस डॉलर/आउंस)

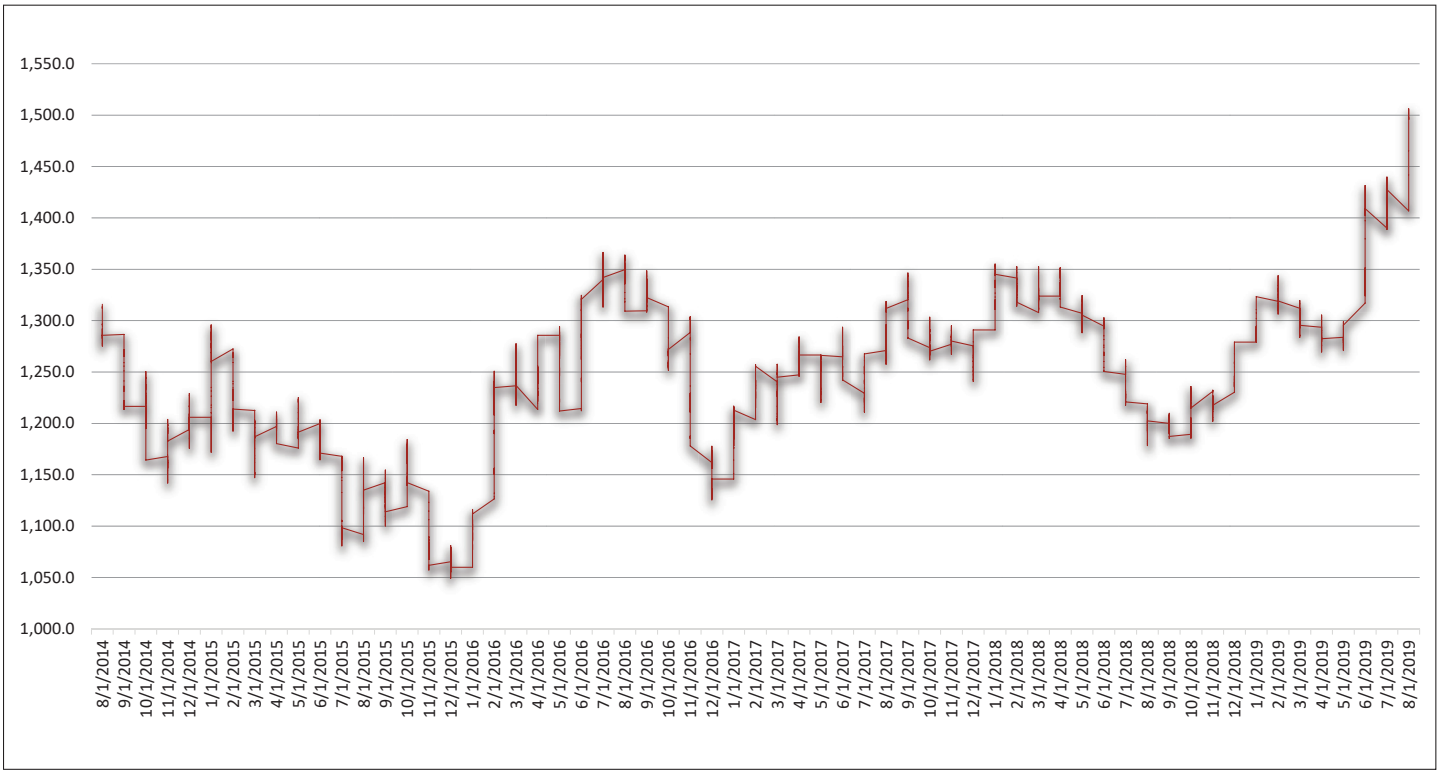

स्रोतः विश्व स्वर्ण परिषद् (वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल)

1 विश्व स्वर्ण परिषद् (वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल)
2 एमसीएक्स
3 विश्व स्वर्ण परिषद (वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल) डाटा

वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर की गई कटौती (उदाहरण के लिए हाल में फेडरल रिजर्व द्वारा की गई 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, आरबीआई द्वारा की गई 35 बेसिस पॉइंट की कटौती और रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड द्वारा ब्याज दर में की गई कटौती), ने लगभग 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर के वैश्विक ऋणों को नकारात्मक क्षेत्र में धकेल दिया, जिससे सोने की मांग में और तेजी आ गई। 1 जनवरी, 2019 से 14 अगस्त, 2019 तक सोने की कीमतें 31,414 रुपये से बढ़कर 38,109 रुपये हो गईं और तदनुसार जनवरी 2019 से सोने में निवेश पर उच्चतम रिटर्न (21.3 प्रतिशत) बना हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे अन्य निवेश क्षेत्रों में जनवरी 2019 से क्रमशः 3.7 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

व्यापार युद्ध

यूएस और चीन के बीच व्यापार युद्ध से भी सोने की कीमतों में जबर्दस्त उछाल आया है। युआन और रुपया, अर्जेंटीना पेसो आदि जैसी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में हाल में आई गिरावट ने सोने की कीमतों में अस्थिरता को प्रभावित किया है। मुद्रा के अवमूल्यन से घरेलू कीमतें बढ़ जाती हैं (क्योंकि सोने की वैश्विक कीमतें यूएस डॉलर में हैं)। सोने की घरेलू कीमतों में बढ़ोत्तरी की एक वजह रुपये की क्रय शक्ति में आई गिरावट भी है, जिसे मुद्रा के अवमूल्यन के ही एक रूप में देखा जा सकता है। यूएस द्वारा चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाने और जवाब में चीन द्वारा भी यूएस के सामान पर आयात शुल्क लगाने से वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी।

एक और वैश्विक मंदी की आहट ने भी बाजारों में निवेशकों के भरोसे को हिलाने का काम किया है। विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा वैश्विक आर्थिक वृद्धि दरों के पूर्वानुमान घटा देने और अन्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा भी वैश्विक आर्थिक मंदी की ओर संकेत करने से भी निवेशकों को धक्का लगा है और इन खबरों ने उनके भरोसे को नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया है। बाजार की इन अनिश्चितताओं का यह जोखिम भी सोने में निवेश बढ़ने का प्रमुख कारण रहा है।

विनिमय दर

भारत में सोने की घरेलू कीमतें मुख्य रूप से वैश्विक बाजारों में सोने की कीमतों से प्रभावित होती हैं। साथ ही रुपया व डॉलर की विनिमय दरों में आने वाले उतार-चढ़ाव और सोने पर आयात शुल्क घटने-बढ़ने से भी कीमतों पर असर पड़ता है। क्योंकि भारत की अधिकांश स्वर्ण जरूरतें आयातों से ही पूरी होती हैं। भारत सरकार ने अपने हालिया बजट में सोने पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया था, जिससे भारत में सोने की कीमतें बढ़ गई थीं। यूएस के मुकाबले भारतीय रुपये में गिरावट से आयात की लागत बढ़ गई और परिणामतः भारत में सोने की कीमतों में भी उछाल आया। मूल्यह्रास से डॉलर की तुलना में रुपये में भी अवमूल्यन होता है। इसके चलते भी भारत में सोने की कीमतें बढ़ीं और देश में सोने की कीमतें बढ़ने की संभावना बढ़ गई।

सोने के बाजार भाव तय करने में खुदरा बिक्री भी सबसे प्रभावी कारकों में से एक है। खुदरा बिक्री जैसी भी हो, इसका असर जीडीपी पर पड़ता है, जीडीपी से निवेशकों की भावनाएं प्रभावित होती हैं और उसका असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। आशाओं के विपरीत, खुदरा बिक्री घटने से सोने की कीमतों में बढ़ोत्तरी देखी गई है।

भू-राजनीतिक तनाव

सोने की कीमतों को प्रभावित करने में भू-राजनीतिक परिदृश्य की भी अहम भूमिका होती है। किसी भी तरह के भू-राजनीतिक तनाव से सोने की कीमतें बढ़ने की आशंका रहती है, क्योंकि निवेशक जोखिम वाली आस्तियों को निकालने की जुगत देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्व में जारी भू-रातनीतिक संकट ने सोने की कीमतें बढ़ा दी हैं। इसी तरह, सितंबर 2019 में सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले के तुरंत बाद भी सोने की कीमतें बढ़ गई थीं। इन हमलों के बाद सोने की कीमतों में 1 प्रतिशत से अधिक का उछाल आया था।

आगे की राह

सोने को मनी मार्केट में अस्थिरता के विरुद्ध हेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मध्यम अवधि में इसकी कीमतें पांच कारकों से निर्धारित होनी जारी रहेंगी। ये पांच कारक हैं- सोने का पूर्ण मूल्य रुझान, सिल्वर ट्रैजेक्ट्री, यूएस डॉलर में गिरावट / मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और एस एंड पी 500 के समक्ष सोने का तुलनात्मक प्रदर्शन।

यूएस-चीन के बीच व्यापार युद्ध में यूएस व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा चीनी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ोत्तरी को टालने के निर्णय के बाद इसे लेकर चिंताएं कुछ कम हुईं और सोने की कीमतों में कुछ नरमी देखी गई तथा निकट भविष्य में फिलहाल कीमतें ऐसी ही बने रहने का पूर्वानुमान है। इसे एस एंड पी 500 द्वारा बेहतर प्रदर्शन वाली सूची में रखा गया है और इस स्थिति के बने रहने की उम्मीद है। सोने की कीमतों में उछाल के लिए इक्विटी बाजारों का आशा से कम निष्पादन जरूरी है।

अल्पावधि में, यूएस द्वारा चीनी कंपनियों को यूएस एक्सचेंज में लिस्टिंग से न रोकने के निर्णय के चलते सोने की कीमतों में भी गिरावट का पूर्वानुमान है। तथापि, रुझान बताते हैं कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि को लेकर चिंताओं, यूएस-चीन व्यापार सौदों में अनिश्चितताओं और केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीतियों में नरमी बरतने के कयासों के चलते मध्यम अवधि में सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। त्यौहारी सीजन के चलते सोने की खुदरा बिक्री बढ़ने की उम्मीदों के चलते पूर्ववर्ती कीमतों में कुछ सुधार की आशा की जा सकती है।

6 बढ़ता व्यापार संरक्षणवाद: भारत पर असर

यूएस और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के अधिकांश हिस्से को प्रभावित कर रहा है। बेहद एकीकृत और वैश्वीकृत व्यापार व्यवस्था में दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा ऐसी संरक्षणवादी नीति अपनाने के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दूरगामी परिणाम होते हैं। वैश्विक मंदी का भारत से निर्यातों पर बहुत अधिक असर पड़ता है और बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद के प्रति भी ये अतिसंवेदनशील होते हैं। इन बाधाओं से पार पाने के लिए और व्यापार युद्ध से प्रभावित यूएस तथा चीन के बाजारों में अपना व्यापार बढ़ाते हुए इसका लाभ उठाने के लिए भारत को एक सुदृढ़ निर्यात रणनीति की आवश्यकता है।

भारत से निर्यातों का विस्तार

यूएस और चीन द्वारा मुख्य रूप से मशीनरी, यांत्रिक साधनों और इलेक्ट्रिकल उपकरणों जैसे क्षेत्रों में टैरिफ लगाए गए है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन क्षेत्रों में भारत का स्पर्धात्मक लाभ और निर्यात योग्य सरप्लस काफी कम है। देखा जाए तो इन उत्पाद श्रेणियों में भारत का व्यापार घाटा रहता है। इसलिए इन प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार अंतरों का लाभ उठाने के मामले में भारत अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले पिछड़ जाता है। तथापि, टैरिफ प्रभावित कुछ क्षेत्र हैं, जिनमें भारत के निर्यातों को प्रतिस्पर्धी बढत हासिल है और इन क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाकर लघु या मध्यम अवधि में निर्यात बढ़ाया जा सकता है।

एक्ज़िम बैंक के एक शोध पत्र के अनुसार, भारत लघु से मध्यम अवधि में, यूएस में लगभग 29.1 बिलियन यूएस डॉलर और चीन में लगभग 2.9 बिलियन यूएस डॉलर के बाजार को भुना सकता है। यूएस बाजार के लिए कुल 33 उत्पादों और चीन के बाजार के लिए 12 उत्पादों को चिह्नित किया गया है। ये ऐसे उत्पाद हैं, जिनमें भारतीय निर्यात स्पर्धात्मक स्थिति में हैं और यूएस व चीन के लिए भारत पहले से ही महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है तथा भारत के लिए इन बाजारों में अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

यूएस को भारत से निर्यातों के लिए चिह्नित इन उत्पादों में तैयार टेक्सटाइल्स, गृह टेक्सटाइल्स (हस्तशिल्प उत्पादों सहित), आभूषण, समुद्री उत्पाद तथा विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान शामिल हैं। यूएस द्वारा आयात किए जाने वाले कुछ टेक्सटाइल उत्पाद ऐसे हैं, जिनमें आधे से ज्यादा भारत और चीन द्वारा ही यूएस को निर्यात किए जाते हैं। ऐसे में यूएस द्वारा चीन पर टैरिफ लगाए जाने से भारत के लिए बड़े बाजार के द्वार खुल सकते हैं। यूएस द्वारा हाल में चीन पर लगाए गए ये टैरिफ भारतीय रत्न एवं आभूषण निर्यातकों के लिए भी अवसरों को बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि इनके जरिए यूएस ने चीन से रफ और पोलिश किए हुए हीरों, सिंथेटिक रत्नों और विभिन्न आभूषणों को अपने बाजार में आने से रोकने के प्रयास किए हैं।

भारत के लिए चीनी बाजार में सबसे ज्यादा अवसर कपास, कार्बनिक रसायनों, हल्के तेल और पेट्रोलियम उत्पाद, पॉलीप्रॉपलीन पॉलीमर तथा विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों में विद्यमान हैं। इन चिह्नित उत्पादों के अतिरिक्त, भारतीय निर्यातकों के चीन के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी अवसर विद्यमान हैं। ये अवसर चीनी प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान इस क्षेत्र में नियमों में नरमी बरतने के चलते विशेष रूप से बढ़ जाते हैं।

भारत से निर्यातों का विस्तार

यूएस और चीन के बीच व्यापार युद्ध से मूल्य श्रृंखला के एकीकरण के अवसर भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला में आए परिवर्तनों के चलते वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भी परिवर्तन आए हैं। चीन में बढ़ती आर्थिक अस्थिरता के कारण चीन से विनिर्माण गतिविधियों के अब तुलनात्मक रूप से स्थिर और सुरक्षित नीतिगत परिवेश वाली अर्थव्यवस्थाओं में स्थानांतरित होने की संभावना है। इससे अन्य के साथ- साथ ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अवसरों के द्वार खुलने की संभावना है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए व्यवसाय परिवेश में सुधार के साथ-साथ इन क्षेत्रों में भारत के विनिर्माण को सुदृढ़ करना प्रमुख कार्यों में से एक होगा।

भारत के लिए बाधाएं

यद्यपि टैरिफ प्रभावित बाजारों में भारतीय निर्यातकों के लिए अवसर विद्यमान हैं, किन्तु बढ़ते संरक्षणवाद से निपटने के लिए भारत अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। मार्च 2018 में यूएस द्वारा स्टील और एल्यूमीनियम पर लगाए टैरिफ और जून 2019 में जीएसपी लाभों को हटाने का असर भारत पर भी पड़ा था। इसके अतिरिक्त, भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर वर्तमान में यूएसटीआर स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल है। यद्यपि बहुत मुमकिन है कि टैरिफ का प्रभाव बढ़ने और भारत का जीएसपी से बाहर निकलने का भारत पर बहुत अधिक असर न पड़े, किन्तु धारा 301 के अंतर्गत भारत के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही का यूएस को भारत द्वारा किए जाने वाले निर्यातों पर बहुत अधिक असर पड़ेगा।

इसलिए, भारत को भविष्य में आने वाली अनिश्चितताओं के प्रति तैयार रहने की आवश्यकता है। साथ ही दूरगामी दृष्टि से बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अपनी निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा विशाखन पर फोकस करने की भी जरूरत है। इसके अतिरिक्त, भारत को निर्यातों को प्रोत्साहित करते हुए और अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाकर व्यापार युद्ध से उभरने वाले अवसरों को भुनाने की जरूरत है। साथ ही बड़े व्यापार करारों के जरिए व्यापार भागीदारों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने, जीवीसी में प्रतिभागिता बढ़ाने और डब्ल्यूटीओ विवाद निपटारा प्रक्रिया को पुनः संशोधित कराने के लिए सहयोग करने की भी जरूरत है।

उदारीकरण, वेतन और क्षेत्रवार वृद्धिः भारत के संबंध सामान्य संतुलन विश्लेषण

भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने 1989 में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक (ईरा) पुरस्कार स्थापित किया था। इस पुरस्कार का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार तथा विकास व संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों द्वारा भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों में शोध एवं विश्लेषण को बढ़ावा देना है। उदारीकरण, वेतन और क्षेत्रवार वृद्धिः भारत के संबंध सामान्य संतुलन विश्लेषण शीर्षक वाला शोध अध्ययन आईआईटी खड़गपुर में अर्थशास्त्र, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉ. सौम्यतनु मुखर्जी की 2018 की ईरा पुरस्कार विजेता थीसिस पर आधारित है।

उदारीकृत व्यापार नीतियां अलग-अलग क्षेत्रों में उत्पादक संस्थाओं पर अलग-अलग माध्यमों के जरिए विशेष असर डाल सकती हैं। तदनंतर इनका असर गरीबी रेखा से नीचे अथवा इससे ठीक ऊपर के आय वर्ग में कृषि अथवा गैर-कृषि वाले अनौपचारिक क्षेत्रों में लगे कार्यबल के एक बड़े हिस्से पर पड़ता है। इस सामान्य संतुलन फ्रेमवर्क में, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं जैसे घरेलू फैक्टर वाले बाजारों में द्विविधता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैर-व्यापारिक सामान की सह-मौजूदगी, का विश्लेषण किया गया है, जिसमें भारत जैसे विकासशील देश के लिए व्यापार की ढांचागत विशेषताएं और उत्पादन पद्धतियां शामिल हैं।

भारत जैसी विकासशील और उदारीकृत अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्रों में रोजगारविहीन वृद्धि देखी जा सकती है, जो कृषि द्विविधता और गैर-व्यापारिक मध्यवर्ती सामग्री के साथ ग्रामीण-शहरी पलायन की द्योतक है। इसलिए, सरकार को उदारीकरण की इन अलग-अलग नीतियों को सावधानीपूर्वक लागू करना चाहिए। व्यापार सुगमता की अलग-अलग नीतियों के परिणामस्वरूप, देखा गया है कि संगठित क्षेत्रों में विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इससे उन्हें श्रम कानूनों में नरमी (उत्पादन में मशीनों का उपयोग करने की आजादी) बरतने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणामतः अकुशल मजदूरों की संख्या में कमी आएगी और इन क्षेत्रों में रोजगारविहीन वृद्धि होगी।

औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण संबंधी विषयों को लेकर भारत सहित अन्य विकासशील देशों की विवादास्पद नीति को लेकर छिड़े विवाद का भी इस थीसिस में गहन विश्लेषण किया गया है। यह देखा गया है कि एफडीआई के लिए मानदंडों को आसान बनाने की सरकारी नीति के चलते विदेशी पूँजी आने से उद्योगों का विस्तार होता है और परिणामतः संसाधनों के पुनः आवंटन के जरिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में बड़े स्तर पर पर्याप्त वृद्धि दर्ज की जा सकती है तथा सामान्य मजदूरी में गिरावट के बावजूद शहरी बेरोजगारी कुछ कम हो सकती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) वस्तुओं के लिए मांग में हल्की सी बढ़ोत्तरी से भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय बढ़ सकती है और इसके साथ ही (एसईजेड) से निर्यात भी बढ़ सकता है। यह देखा गया कि एक खुली अर्थव्यवस्था में समान परिस्थितियों से शुरू करने वाली छोटी, एसईजेड युक्त अर्थव्यवस्था के बिना एसईजेड वाळी अर्थव्यवस्था की तुलना में वृद्धि की संभावनाएं अधिक रहती हैं। हालाकि वास्तविक वेतन आय में होने वाली कमी से ग्रामीण मजदूरों (गैर-प्रवासी) पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए, यह नीति मिश्रित परिणामों की ओर संकेत करती है और वंचितों तथा ग्रामीण मजदूरों के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

भारत में 1991 में हुए आर्थिक सुधारों का भारत के शहरी संगठित क्षेत्रों के प्रौद्योगिकीय सुधार में अहम योगदान रहा है, जो हाल के कुछ वर्षों में काफी बढ़ा है। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच मजबूत अंतर-संबंधों के बावजूद, उत्पादकता संगठित क्षेत्र में ही बढ़ी है और शहरी अनौपचारिक क्षेत्र के वेतन में हाल के वर्षों में हुई तीव्र वृद्धि अब भी एक पहेली बनी हुई है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र से पूँजी और श्रम दोनों कम हो रहे हैं।

इसी प्रकार, कौशल गहन क्षेत्रों में तेज वृद्धि भारत में उदारीकरण के सबसे महत्त्वपूर्ण प्रभावों में से एक है। वहीं दूसरी ओर, उदारीकरण ने मशीनरी के आयात को सुगम बनाया और उन आयातित मशीनों के साथ विदेशी प्रौद्योगिकी भी भारत आई। विदेशी प्रौद्योगिकी आने के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त कौशल की मांग उत्पन्न हुई। इससे कुशल कार्यबल की मांग बढ़ी और कुशल कामगारों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी हुई। इस संदर्भ में, इस अध्ययन में कौशल गहन क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र के वेतन और रोजगारों पर व्यापार आधारित ऐसी वद्धि के सामान्य संतुलन प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। साथ ही इसका भी अध्ययन किया गया है कि यह प्रभाव फिनिश्ड गैर-व्यापारिक तथा तदनुरूपी घरेलू मांग-आपूर्ति बलों के जरिए किस रूप में पड़ा।

इस मॉडल के जरिए कुशल श्रमिकों की बेरोजगारी के संबंध में भी विश्लेषण किया गया है, जिसके लिए उनकी योग्यता और वेतन को आधार बनाया गया है। इसमें पाया गया कि अच्छे वेतन से कुशल व्यक्ति ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित होता है, जबकि उच्चतर बेरोजगारी दर नौकरी से निकाले जाने के भय से अनुपयोगिता को बढ़ाती है, जो कुशल व्यक्ति को अधिक अनुशासित करती है।

इस एक्सटेंडेड मॉडल में भी इसी तरह पूर्ण-बेरोजगारी परिदृश्य में, अतिरिक्त आपूर्ति-प्रभाव है, जो अनौपचारिक क्षेत्र में अकुशल व्यक्तियों के वेतन को हतोत्साहित करता है और गैर-व्यापारिक उत्पादन में अस्पष्टता बढ़ती है। इसलिए, शहरी आबादी की वास्तविक आय पर प्रभाव और गैर-व्यापारिक उत्पादों की मांग में भी अस्पष्टता होगी। नतीजतन, प्रतिस्पर्धी अनौपचारिक वेतन में होने वाले परिवर्तन की दिशा और उसके कारण आय-असमानता में होने वाले परिवर्तन की दिशा (गिनी-कोएफिशिएंट) भी अस्पष्ट होगी।

एक्ज़िम बैंक का ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) कार्यक्रम

एक्ज़िम बैंक अपने ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण भारत के ग्रासरूट उद्यमों के वैश्वीकरण में सहायता देता है। इस प्रकार देश के समृद्ध पारंपरिक कला और शिल्प को सहेजने के साथ-साथ शिल्पकारों को स्थायी आजीविका बनाने में भी सहायता करता है।

घरेलू बाजार में ग्रामीण दस्तकार सामान्य तौर पर हाशिये पर रहते हैं। उन्हें अपनी कला का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। फिर चाहे वह घरेलू बाजार हो या विदेशी। इनकी दूसरी समस्या यह भी है कि इन बाजारों तक पहुंचने के लिए इनकी लागत बढ़ जाती है। न उनके पास बाजारों की समुचित जानकारी है और न ही उन बाजारों में व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त कुशलता। उनमें एक संगठनात्मक ढांचे का भी अभाव है, जिसके जरिए बड़े बाजारों के मध्यस्थों से संपर्क किया जा सके। नई तकनीकी, डिजाइन पैकेजिंग और मार्केटिंग में विशेषज्ञता का अभाव तो बना ही रहता है। भारत की कई पारंपरिक कलाएं मशीनीकरण, आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास के चलते विलुप्त होने की कगार पर थीं। भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों की इन कलाओं के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव भी इसका एक बड़ा कारण है।

ग्रिड कार्यक्रम देश के ग्रामीण शिल्पकारों, दस्तकारों, उद्यमियों, उत्पादक समूहों, क्लस्टरों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए अवसरों का विस्तार करता है। बैंक ग्रासरूट उद्यमों को उत्पाद विकास / बिजनेस साइकल के अलग-अलग चरणों में सहायता करते हुए इनके लिए अवसरों के नए द्वार खोलता है। बैंक क्षमता विकास, प्रशिक्षण, निर्यात क्षमता सृजन, विस्तार / उनके ग्राहकों का विशाखन और निर्यातों में आने वाले उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए उनका सहयोग करता है।

ग्रासरूट उद्यमों के उत्पादों को निर्यात कराने में मदद करने और उन उत्पादों की अच्छी कीमत सुनिश्चित करने के अलावा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रासरूट उद्यमों में परिचालन क्षमता का विकास करना, नई तकनीकी तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना और डिजाइन / पैकेजिंग में विशेषज्ञता दिलाना भी है, ताकि उनके उत्पादों का उच्च मूल्य वर्धन हो सके और उन उत्पादों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जा सके।

इसके लिए बैंक अपने ग्रिड कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे ग्रासरूट उद्यमों के लिए अनुदानों और सॉफ्ट लोन के जरिए सहायता प्रदा करता रहा है, जिनमें निर्यातों की संभावनाएं हैं। यह सहायता नवोन्मेषी तकनीकी के विकास के लिए भी दी जाती है। इस कार्यक्रम के जरिए बैंक ने अधिक से अधिक ग्रासरूट संगठनों तक सीधे पहुंचने के उद्देश्य से संस्थागत संबंध बनाए हैं, सहयोग ज्ञापन भी किए हैं और क्षमता विकास तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, बाजार तक पहुंच तथा प्रशिक्षण के माध्यम से इन उद्यमों को सहयोग प्रदान किया है। एक्ज़िम बैंक के ग्रासरूट उद्यम विकास कार्यक्रम से 1,10,000 से अधिक ग्रामीण उत्पादक लाभान्वित हुए हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए:
grid@eximbankindia.in

एक्ज़िम बैंक के ग्रिड कार्यक्रम को मिला पुरस्कार

एक्ज़िम बैंक के ग्रासरूट उद्यम विकास कार्यक्रम (ग्रिड) को यूरोपीयन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा 11 जुलाई, 2019 को आयोजित ग्लोबल सस्टेनेबल फायनैंस अवॉर्ड्स (जीएसएफए) के दौरान द कार्लज़ूए सस्टेनेबल फायनैंस अवॉर्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम जर्मनी के कार्लज़ूए के सिटी हॉल में आयोजित किया गया था। यह पुरस्कार ऐसे वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, जिनमें 3P - पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट का का ध्यान रखा जाता है। इस श्रेणी में विजेताओं को अपने ऋण कार्यक्रमों / जमा उत्पादों अथवा अन्य वित्तीय सेवाओं के जरिए लोगों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाना होता है।

एक्ज़िम बैंक और सर्व शांति आयोग के बीच सहयोग ज्ञापन

कोलकाता स्थित सर्व शांति आयोग एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो 1978 में बना था। इसके बाद 1987 में साशा एसोसिएशन फॉर क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स का गठन हुआ। वर्तमान में एसएसए और साशा देशभर में 5000 दस्तकारों व 100 से ज्यादा शिल्प उद्यमों के साथ मिलकर 16 तरह की शिल्प कलाओं में काम कर रहे हैं। एसएसए मुख्य संगठन है और साशा एसोसिएशन फॉर क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स डेवलपमेंट पार्टनर है, जो ग्रासरूट उद्यमों को विशेष बाजारों तक पहुंचाने का काम करता है। वहीं, एसएसए व्यवसाय क्षमता विकास पर काम करता है। साशा वर्ल्ड फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गारंटी प्राप्त सदस्य है। यह सर्व शांति आयोग के साथ मिलकर काम करता है, जिसने शिल्प को जीवन के अमूल्य हिस्से के रूप में नई पहचान दिलाई है। साशा और एसएसए पारंपरिक और प्रोफेशनल शिल्प को बढ़ावा देते हैं तथा शिल्पकारों को व्यवसाय के विभिन्न अवसर प्रदान कर उनका सशक्तिकरण करते हैं तथा कला एवं शिल्प को शिक्षा के जरिए बढ़ावा देते हुए बड़े फलक तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं।

एक्ज़िम बैंक और एसएसए के बीच 19 अगस्त, 2019 को एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक्ज़िम बैंक तथा एसएसए दोनों ही ग्रासरूट उद्यमों को बढ़ावा देते हैं और उनमें वैश्विक स्तर की निर्यात स्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। एसएसए और बैंक भारत और विदेशी बाजारों के लिए नवीनतम ट्रेंड वाले डिजाइन विकसित करने और ग्रासरूट स्तर के उद्यमों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। दोनों के बीच उक्त सहयोग ज्ञापन से दोनों संस्थाओं की ग्रासरूट पहलों को बढ़ावा मिलेगा तथा परस्पर सहयोग से दोनों संस्थाएं एक साथ मिलकर पारंपरिक तथा व्यावसायिक क्राफ्ट को बढ़ावा दे सकेंगी। दोनों संस्थाएं विभिन्न तरह के व्यावसायिक अवसरों के जरिए शिल्पकारों को स्थाई आजीविका मुहैया कराने सहित इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में भी मदद करेंगी। इस सहयोग ज्ञापन के जरिए बेहतर निर्यात क्षमता वाले ग्रासरूट उद्यम बेहतर गुणवत्ता में निवेश के लिए एक्ज़िम बैंक से वित्त भी प्राप्त कर सकते हैं।

एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातक को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो। ऋण–व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण–व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। बैंक द्वारा अब तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया और सीआईएस क्षेत्रों के 63 देशों को 24.97 अरब यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 255 ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण–व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्द्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

एक्ज़िम बैंक ने जुलाई–सितंबर 2019 के दौरान भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित तीन ऋण–व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए:

(i) भारत सरकार की ओर से बुरुंडी सरकार को 161.36 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की गई है। यह ऋण–व्यवस्था बुरुंडी के गितेगा में संसद भवन और मंत्रालयी भवनों के निर्माण के लिए प्रदान की गई है। उक्त ऋण–व्यवस्थाओं सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से बुरुंडी सरकार को अब तक कुल 283.74 मिलियन यूएस डॉलर की चार ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इन ऋण–व्यवस्थाओं के जरिए बुरुंडी में जल विद्युत परियोजना, कृषि यंत्रीकरण के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(ii) क्यूबा सरकार को क्यूबा में 75 मेगावाट के फोटोवोल्टिक सोलर पार्क की स्थापना के लिए 75 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की गई। उक्त ऋण–व्यवस्था सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से क्यूबा सरकार को अब तक कुल 248.06 मिलियन यूएस डॉलर की छह ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इन ऋण–व्यवस्थाओं के जरिए क्यूबा में दूध पाउडर प्रसंस्करण संयंत्र, बल्क ब्लेंडिंग फर्टिलाइजर प्लांट, इन्जेक्टेबल प्रोडक्ट्स प्लांट, 51 मेगावाट के पवन ऊर्जा फार्म और 50 मेगावाट के सह–उत्पादन पॉवर प्लांट संबंधी परियोजनाओं के लिए सहयोग प्रदान किया गया है।

(iii) सूरीनाम सरकार को डी मेल्कसेन्ट्राले एन.वी. दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के पुनरुद्धार और उन्नयन के लिए 11.13 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की गई है। उक्त ऋण–व्यवस्था सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से सूरीनाम सरकार को अब तक 89.18 मिलियन यूएस डॉलर की कुल आठ ऋण–व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण–व्यवस्थाएं सूरीनाम सरकार को हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति, बिजली व जल आपूर्ति, ट्रांसमिशन लाइनों के उन्नयन तथा विद्युत उत्पादन संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए

श्री सुदत्त मंडल,
मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय निर्यात–आयात बैंक,
ऑफिस ब्लॉक, टावर 1, 7वीं मंजिल
एड्जेसेंट रिंग रोड
किदवई नगर (पूर्व)
नई दिल्ली – 110023
टेलीफोनः (011) 24607700
ई–मेल : eximloc@eximbankindia.in

दास्तान–ए–कामयाबी: मलावी

मलावी सरकार को मुलांजे में लिखुबुला नदी से ब्लैंटायर तक जल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण के वित्तपोषण के लिए 23.50 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण–व्यवस्था प्रदान की गई है। 23.44 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की इस परियोजना का उद्घाटन 18 अक्टूबर, 2019 को गुलुंडी में किया गया। यह परियोजना एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निष्पादित की जा रही है। इस परियोजना में लिखुबुला नदी पर जल भंडारण ढांचे का निर्माण कार्य; नदी से गुलुंडी, जो ब्लैंटायर से नजदीक है, तक 50 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने संबंधी कार्य; शहर में पिंगवे हिल पर एक स्टोरेज टैंक का निर्माण और इस स्टोरेज टैंक से ब्लैंटायर में दो जगहों पर आपूर्ति व्यवस्था करने जैसे कार्य शामिल हैं।

मलावी के ब्लैंटायर शहर को पानी की बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना से जल भंडारण क्षमता 96,000 क्यूबिक मीटर से बढ़कर 116,000 क्यूबिक मीटर तक होने की उम्मीद है। इससे आने वाले समय में पानी की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी और ब्लैंटायर तथा आसपास के इलाकों में रहने वाले लगभग 3 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। दरअसल ब्लैंटायर में लगातार तेजी से बढ़ती आबादी के कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करने की क्षमता फिलहाल शहर में नहीं है। इस परियोजना का उद्देश्य पानी की किल्लत को दूर करना है। लंबी अवधि में देखा जाए तो इस परियोजना से बिजली की लागत में भी कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि यह सिस्टम गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए रॉ वॉटर ट्रांसमिशन मेन्स के माध्यम से संचालित होगा।

जल शोधन संयंत्र का मुख्य नियंत्रण कक्ष

32 बिलियन जापानी येन के दो बॉन्ड निर्गमों के साथ समुराई बॉन्ड बाजार में सफलतापूर्वक लौटा एक्ज़िम बैंक

एक्ज़िम बैंक ने समुराई बॉन्ड बाजार में सफलतापूर्वक वापसी कर ली है। बैंक ने यह वापसी 32 बिलियन जापानी येन के तीन साल और पांच साल के लिए फिक्स दरों के डबल ट्रांच ट्रांजैक्शन के साथ की है। समुराई बॉन्ड जापानी बाजार में विदेशी सरकार, एजेंसी या कंपनी द्वारा जारी जापानी येन राशि के बॉन्ड होते हैं। इनकी कूपन दरें क्रमशः 0.59% और 0.66% प्रति वर्ष तय की गई थीं। यह ट्रांजैक्शन, 2006 के बाद एक्ज़िम बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी के जारी किया गया समुराई बॉन्ड निर्गम है। यह निर्गम दर्शाता है कि 2011 और 2014 में जेबिक द्वारा गारंटित समुराई बॉन्ड और जापानी रिटेल निवेशकों को लक्षित जापानी येन सहित विभिन्न मुद्राओं में उरीदाशी बॉन्ड जारी करते हुए एक्ज़िम बैंक ने अपनी ऋण साख और पहचान बनाए रखी है। दाइवा सिक्योरिटीज कंपनी लिमिटेड, मितसुबिशि यूएफजे मॉर्गन स्टैनले सिक्योरिटीज़ कंपनी लिमिटेड, मिज़ुओ सिक्योरिटीज कंपनी लिमिटेड और एसएमबीसी निक्को सिक्योरिटीज इंक बिक्री के लिए संयुक्त लीड मैनेजर हैं।

एक्ज़िम बैंक के उप प्रबंध निदेशक देबाशिस मल्लिक अपना कार्यकाल पूरा होने पर कार्यालय के कार्यभार विमुक्त हुए

श्री देबाशिस मल्लिक ने अपना कार्यकाल पूरा हो जाने पर एक्ज़िम बैंक के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) पद से त्याग पत्र दे दिया है। श्री मल्लिक ने 2014 में डीएमडी के रूप में पदभार संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने परियोजना निर्यात, ऋण-व्यवस्था, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी, शोध एवं विश्लेषण सहित विभिन्न परिचालनों का उत्तरदायित्व संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में बैंक ने सभी क्षेत्रों में विशेषकर राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण तथा विदेशी निवेश वित्त में उल्लेखनीय प्रगति की। इसके अलावा श्री मल्लिक ने विभिन्न बहुपक्षीय एवं विदेशी संस्थाओं के साथ एक्ज़िम बैंक के संस्थागत संबंधों को सुदृढ़ किया। उन्होंने तटीय नौपरिवहन, अंतरदेशीय जलमार्गों, नौपरिवहन, बंदरगाहों एवं जेटी, जहाज निर्माण तथा मरम्मत सहित संपूर्ण समुद्रतटीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए एक्ज़िम बैंक की पहल का भी नेतृत्व किया। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के जरिए कुछ हाई प्रोफाइल ऋण खातों सहित बड़ी ऋण वसूलियों में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही निर्यात विकास कोष के अंतर्गत व्यवसाय को पुनः सक्रिय करने में भी उनका अहम योगदान रहा।

एक्ज़िम बैंक ने घोषित किया ईरा पुरस्कार 2018 का विजेता

एक्ज़िम बैंक का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक (ईरा) पुरस्कार 2018 डॉ. सौम्यतनु मुखर्जी के नाम रहा। उन्हें यह पुरस्कार उदारीकरण, वेतन और सेक्टर वृद्धिः भारत के संबंध में समान्य संतुलन विश्लेषण शीर्षक वाली उनकी डॉक्टोरल थीसिस के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार की घोषणा नई दिल्ली में 07 अगस्त, 2019 को आयोजित पुरस्कार समारोह में एक्ज़िम बैंक के प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना द्वारा की गई। इस दौरान बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री टी.सी.ए. रंगनाथन और दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के पूर्व निदेशक और प्रोफेसर एमेरिटस डॉ. के. एल. कृष्णा विशेष रूप से उपस्थित रहे। पुरस्कार के रूप में 3.50 लाख रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर डॉ. सौम्यतनु मुखर्जी की पुरस्कृत थीसिस पर आधारित एक्ज़िम बैंक के प्रासंगिक आलेख का भी विमोचन किया गया।

कोत दि'वार में भारत-कोत दि'वार बिजनेस फोरम का आयोजन

एक्ज़िम बैंक ने आबिदजान में भारतीय दूतावास के सहयोग से कोत दि'वार में ''भारत-कोत दि'वार बिजनेस फोरम'' का आयोजन किया। एक्ज़िम बैंक ने फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी तथा कृषि क्षेत्रों से भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया। इस फोरम में 150 से ज्यादा प्रतिभागी रहे। भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कोत दि'वार के मंत्रालयों, दूसरे उद्योग प्रतिनिधियों तथा कोत दि'वार सरकार की निवेश एजेंसियों के साथ चर्चा में हिस्सा लिया।

एक्ज़िम बैंक का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार

भारत-कोत दि'वार बिजनेस फोरम

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अवसर

तिमाही के दौरान एक्ज़िम बैंक ने भारतीय निर्यात संगठन संघ (फिओ) के साथ मिलकर तीन सेमिनारों का आयोजन किया। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र में निर्यात क्षमता सृजन पर फोकस किया गया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अवसर विषय पर इन सेमिनारों का आयोजन मैसूर (कर्नाटक), रुद्रपुर (उत्तराखंड) और जोधपुर (राजस्थान) में किया गया। इन सेमिनारों में हर शहर में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में सीमा शुल्क विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), ईसीजीसी लिमिटेड से वक्ताओं ने हिस्सा लिया तथा वहां स्थानीय चैंबर्स ऑफ कॉमर्स का भी प्रतिनिधित्व रहा। सेमिनारों में संबंधित राज्यों के लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के चुनिंदा निर्यातकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। अनुभव साझा करने वाला यह सत्र निर्यातकों के अनुभवों से अन्य निर्यातकों को सीखने और नए उद्यमियों को विदेशी बाजारों में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित करने में मददगार रहा।

'छत्तीसगढ़ के लिए निर्यात रणनीति' पर सेमिनार

एक्ज़िम बैंक ने जुलाई 2019 में रायपुर में इंडो-ग्लोबल एसएमई चैंबर के साथ मिलकर 'छत्तीसगढ़ के लिए निर्यात रणनीति' विषय पर सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार में छत्तीसगढ़ के माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा विशेष रूप से उपस्थित रहे। श्री लखमा ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में निर्यातों के योगदान पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, डीजीएफटी और ईसीजीसी लिमिटेड से वरिष्ठ अधिकारी वक्ताओं के रूप में उपस्थित रहे। सेमिनार में रायपुर के अलावा बिलासपुर, अम्बिकापुर तथा भिलाई जैसे पड़ोसी औद्योगिक क्लस्टरों से 80 से ज्यादा एमएसएमई उद्यमियों ने हिस्सा लिया।

एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ऋण-व्यवस्थाओं में व्यवसाय अवसरों पर सेमिनार

विदेश मंत्रालय और एक्ज़िम बैंक ने मिलकर एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ऋण-व्यवस्थाओं में व्यवसाय अवसरों पर सितंबर 2019 में इंदौर में सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के सचिव श्री ए. अजय कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 80 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सेमिनार में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आइडियाज दिशानिर्देशों, एम्पैनलमेंट, पूर्व अर्हता प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट कवरेज के लिए ऋण-व्यवस्था प्रक्रिया, संवितरण और निगरानी, इंजीनियरिंग, बुनियादी ढांचा, निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन, सौर ऊर्जा और सिंचाई एवं जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की गई।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों पर चर्चापरक कार्यशाला

एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक समूह ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ मिलकर विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों पर नई दिल्ली में सितंबर 2019 में चर्चापरक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से प्रोक्योरमेंट विशेषज्ञों सहित एक्ज़िम बैंक के वरिष्ठ अधिकारी फैकल्टी के रूप में उपस्थित रहे। सेमिनार में मुख्य रूप से (i) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों की जानकारी; (ii) आगामी प्रोक्योरमेंट अवसरों की जानकारी (iii) प्रोक्योरमेंट के लिए नीतियां और प्रक्रिया तथा (iv) लिंग आधारित हिंसा संबंधी नीति की जानकारी दी गई।

एक्ज़िम बैंक की मास्टर क्लास

व्यापार, भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था, निर्यात संबंधी विषयों और नीतियों आदि में रुचि रखने वाले अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक्ज़िम बैंक ने मास्टर क्लास का आयोजन शुरू किया है। इस तिमाही के दौरान बैंक ने ऐसी दो मास्टर क्लास का आयोजन किया। 'केंद्रीय बजट का चुनिंदा क्षेत्रों पर प्रभाव' विषयक मास्टर क्लास का आयोजन जुलाई 2019 में किया गया। बैंक के अधिकारी ही इसके वक्ता रहे। अगस्त 2019 में 'कैसे करें निर्यात' विषयक मास्टर क्लास का आयोजन किया गया। इस मास्टर क्लास के वक्ता अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ श्री मिहिर शाह रहे। इसमें निर्यात की आधारभूत बातें समझाई गईं, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर, क्रेताओं को चिह्नित करना, जीएसटी संबंधी मसले, निर्यात के लिए दस्तावेजीकरण, प्रोत्साहन आदि पर बात की गई। इस मास्टर क्लास का आयोजन ग्रासरूट स्तर के उद्यमों तक पहुंचने के उद्देश्य से हिन्दी में किया गया।

जोधपुर में आयोजित सेमिनार 'एमएसएमई के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अवसर'

'एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ऋण-व्यवस्थाओं में व्यवसाय अवसर' सेमिनार

एक्ज़िम बाज़ार के जरिए स्थानीय दस्तकारों को एक्ज़िम बैंक का सहयोग

एक्ज़िम बैंक अपने ग्रासरूट उद्यम विकास कार्यक्रम (ग्रिड) और मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के माध्यम से दस्तकारों, मास्टर कारीगरों, बुनकरों, क्लस्टरों, स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, ग्रासरूट और सूक्ष्म उद्यमों को विभिन्न व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने के लिए सहयोग प्रदान करता रहा है। इन्हीं प्रयासों के क्रम में बैंक ने सितंबर 2017 में एक्ज़िम बाज़ार नाम से एक पहल की। यह हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की अनूठी प्रदर्शनी है, जहां क्रेता सीधे उत्पादक से संपर्क करते हैं। पांचवें एक्ज़िम बाज़ार का आयोजन 27-29 सितंबर, 2019 के दौरान मुंबई स्थित विश्व व्यापार केंद्र में किया गया।

एक्ज़िम बाज़ार देश के विभिन्न हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों (जिनमें से कुछ अपनी-अपनी कलाओं में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं) द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करता है। इससे बाजार में उनकी पहुंच बढ़ती है और संभावित थोक क्रेताओं से चर्चा भी सुगम होती है। कारीगरों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने से ग्राहकों को उस शिल्प और उसमें बसी संस्कृति के बारे में गहराई से जानने का मौका मिलता है।

एक्ज़िम बाजार का एक अन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय पारंपरिक कलाओं और शिल्प को सहेजना और इस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाना में सहयोग करना है, जिनमें से कई आधुनिक अर्थव्यवस्था में विलुप्त होने की कगार पर हैं। बैंक द्वारा सहायता प्राप्त अन्य प्रतिष्ठित कार्यक्रमों की तरह ही 'एक्ज़िम बाज़ार' के व्यापक संवर्धन से भारत की पारंपरिक कलाओं और शिल्प को एक बड़ा ग्राहक आधार प्रदान करने के साथ-साथ लोगों में इनके प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है। एक्ज़िम बाज़ार में हिस्सा लेने से प्रतिभागियों को हजारों ग्राहकों से एक साथ मिलने और आगामी ऑर्डर हासिल करने में मदद मिली। इसके अलावा, कारीगरों को उपभोक्ताओं की पसंद और व्यवहार को समझने, नए संपर्क विकसित करने, नए खरीदारों तक पहुंचने तथा उद्योग की अपनी जानकारी बढ़ाने और नवीनतम रुझानों को जानने में भी मदद मिली।

एक्ज़िम बाज़ार में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 23 से अधिक राज्यों की समृद्ध कलात्मक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 70 प्रतिभागियों ने अपने हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया। तीन दिवसीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित उत्पादों में चमड़े की कठपुतली, मधुबनी, गोंड, कांगड़ा मिनिएचर, पट्टचित्र, फड़, पिछवाई पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग शामिल रहे। वहीं, बस्तर, हस्तनिर्मित कटलरी, नारियल शिल्प, तांबे की घंटी, कच्ची मिट्टी के बर्तन, ढोकरा, केले के फाइबर, चेन्नापटना, बीदरी मेटलवेयर, भित्ति चित्र, वारली, कौना, सिल्वर फिलीग्री, क्रिस्टल जूलरी, धोंक क्राफ्ट, कवाड, लाख, संझी कला, टेराकोटा, वुडन हैंगिंग, सबाई घास उत्पाद, शहद और आंवला, जयपुर जूलरी जैसे शिल्प तथा तसर सिल्क, अजारख, कला कॉटन एंड वूल, एप्लीक, बंधनी, पटोला, कस्तूरी, चंदेरी, हिमरू, पैठनी, इकत साड़ी, फुलकारी, क्रोशिया, लहरिया, शिबूरी, बनारसी, पैचवर्क वाली रज़ाइयां, चिकनकारी, जामदनी, कालीन और कांथा आदि शामिल रहे।

एक्ज़िम बैंक अपने ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) और मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के माध्यम से ग्रासरूट उद्यमों और निर्यात क्षमता वाली अभिनव प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार का (वित्तीय/सलाहकारी) सहयोग प्रदान करता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कारीगरों, उत्पादक समूहों, क्लस्टरों, छोटे उद्यमों और गैर-सरकारी संगठनों की मदद करना है, जो देश की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत के वास्तविक संरक्षक हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य इन उत्पादों के निर्यात में सहयोग कर उन्हें अपने उत्पादों की सही कीमत दिलाना है। साथ ही परिचालनगत दक्षता बढ़ाना, उच्च मूल्य वर्धन हासिल करना और उत्पादों के लिए बड़े बाजार तक पहुंच बढ़ाना तथा सूक्ष्म उद्यमों में कौशल विकास तथा निर्यात बाजार के प्रमाणीकरण हासिल करने में सहयोग करते हुए उनकी निर्यात क्षमता और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता को बढ़ाना इन कार्यक्रमों का एक और उद्देश्य है।

एक्ज़िम बाज़ार 2019 की झलक

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए:
grid@eximbankindia.in

ज़ाम्बिया

ज़ाम्बिया की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर एक वर्ष पूर्व की 4.1% से गिरकर 2018 में 3.1% रही। यह गिरावट खनन क्षेत्र में निवेशों के कम रहने और धीमी वृद्धि की ओर संकेत करती है। वर्ष 2019 में सख्त मौद्रिक स्थितियों, सूखे के कारण कृषि क्षेत्र पर पड़े दुष्प्रभाव और उच्च करों तथा तांबे की कीमतों के स्थिर रहने के कारण खनन क्षेत्र में मंदी के चलते यह वृद्धि दर गिरकर 0.8% रहने की आशंका है। कम बारिश के कारण मकई की फसल खराब रहने के चलते उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2019 में 9.0% रहने की उम्मीद है। यदि ऐसा हुआ तो यह बैंक ऑफ ज़ाम्बिया के 6-8% के लक्ष्य के प्रतिकूल होगी। एफडीआई में गिरावट, लगातार घटते-बढ़ते बजट घाटे के कारण निवेशकों द्वारा पूँजी निकालने और उच्च राजकोषीय जोखिम के चलते ज़ाम्बिया की मुद्रा क्वाचा के भी अवमूल्यन की आशंका है। 2019 के आखिरी में पॉवर टैरिफ लागू होने की उम्मीद है। किन्तु किसी कारणवश यदि ये लागू नहीं होते हैं तो सरकारी कंपनी ज़ेस्को के कर्ज में डूबने का जोखिम बढ़ जाएगा। टैरिफ बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। वर्ष 2019-23 के दौरान ज़ाम्बिया की आर्थिक वृद्धि दीर्घावधि में देश की संभावनाओं से काफी कम रहेगी। खनन रॉयल्टी की उच्चतर दरें, वैट में मिलने वाली छूट हटाने और केसीएम के जबरन परिसमापन से तांबे के खनन क्षेत्र में निवेश कम होगा। यूएस डॉलर के मुकाबले क्वाचा के भी लगातार गिरने की आशंका है। इसकी एक वजह संप्रभु जोखिम बढ़ने और चालू खाता घाटा बढ़ने के चलते विदेशी निवशकों द्वारा पूँजी निकालना भी है।

वियतनाम

वियतनाम की अर्थव्यवस्था में निर्यात केंद्रित विनिर्माण और प्रसंस्करण क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है। वियतनाम की विकास दर 2018 में 7.1% थी, जो 2019 में 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण विशेष रूप से यूएस जैसे प्रमुख बाजारों से मांग में कमी आना है। तथापि, वियतनाम आसियान क्षेत्र में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा और यहां से निर्यात भी अच्छा रहेगा। वियतनाम खुद को निर्यात उन्मुख विनिर्माण (चीनी कंपनियों रे बीच भी) क्षेत्र में चीन से भी किफायती देश के रूप में स्थापित करने में सफल रहा है। अतः यूएस और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध का लाभ वियतनाम को मिलेगा और निर्यात संबंधी विनिर्माण चीन से वियतनाम के हिस्से आएंगे। यह बहुपक्षीय कंपनियों द्वारा निवेश और निर्यात, दोनों के बढ़ने का मुख्य कारण रहेगा। निर्यात उन्मुख उत्पादन क्षमता बढ़ने से 2019-20 में विदेशी मांग के कमजोर होने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर कम पड़ेगा। वैश्विक तेल कीमतों में आई गिरावट के चलते वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दर 2018 में 3.5% से घटकर वर्ष 2019 में 2.6% रहने की उम्मीद है। मध्यम अवधि के दौरान वियतनाम का वस्तु व्यापार सरप्लस होने की उम्मीद है, जो विनिर्माण निर्यातों के मूल्य वर्धन को प्रदर्शित करता है। फेडरल रिज़र्व द्वारा मौद्रिक नीति में नरमी बरतने और यूएस की अर्थव्यवस्था में मंदी की निवेशकों की चिंता के बीच 2020 और 2021 में यूएस डॉलर के कमजोर होने के बावजूद डॉलर के मुकाबले वियतनाम की मुद्रा डोंग में गिरावट की आशंका है। वर्तमान चालू खाता सरप्लस निर्यात विनिर्माण क्षेत्र में मूल्य वर्धन को प्रदर्शित करते हुए 2019 में जीडीपी के 1.7% के मुकाबले 2020 में बढ़कर 2.3% होने की उम्मीद है।

ब्राजील

ब्राजील का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2020-23 के दौरान 2.2% की वार्षिक औसत दर से बढ़ने का अनुमान है। श्रम बाजार में धीरे-धीरे आते सुधार और ऋण वृद्धि के चलते वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी की उम्मीद है। किन्तु यूएस अर्थव्यवस्था में मंदी और अर्जेंटीना के आर्थिक संकट के चलते जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट का जोखिम भी बना हुआ है। सुदृढ़ नीतिगत फ्रेमवर्क और मुद्रास्फीति दर के अनुसार न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी के चलते वर्ष 2020-24 के दौरान उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दर स्थिर रहने के आसार हैं। समय-समय पर पड़ने वाली मौसम की मार के चलते खाद्यान्न में आई कमी और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दर को नियंत्रण में रखना चुनौती होगी। वर्ष 2020 में ब्राजील की मुद्रा रियाल का मूल्य एक यूएस डॉलर के मुकाबले 3.93 रियाल और 2024 के अंत तक गिरकर 4.15 रियाल रहने का अनुमान है। आर्थिक सुधारों को लागू न किए जाने की सूरत में यूएस डॉलर के मुकाबले रियाल के मूल्य में और अधिक गिरावट आने का जोखिम बना हुआ है। घरेलू मांग में सुधार आने और आयातों के बढ़ने से व्यापार अधिशेष (सरप्लस) 2018 में जीडीपी के 2.8% से घटकर 2024 में 0.8% हो जाने का अनुमान है। प्राथमिक आय घाटा 2020-24 में जीडीपी का औसत 2.1% रहेगा, जो लाभ रेमिटैंस और कर्ज चुकौती को प्रदर्शित करता है और सेवा घाटा औसत 2.2% रहेगा। इनके चलते 2023 तक चालू खाता घाटा 2.9% हो जाएगा।

मिस्र

मिस्र की जीडीपी वृद्धि दर 2018 में 5.3% थी, जो 2019 में बढ़कर 5.5% हो गई। तथापि, वैश्विक मांग में कमी आने के चलते 2020 में इसके घटकर 4.8% रहने का पूर्वानुमान है। निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र का मिस्र की विकास दर में महत्त्वपूर्ण योगदान है। दीर्घावधि के संबंध में देखा जाए तो 2022-24 के दौरान हाइड्रोकार्बन संसाधनों के विकास और प्रसंस्करण क्षमताएं बढ़ने से वृद्धि दर 5.7% तक हो सकती है। मिस्री पाउंड का मूल्य 2018 में जहां एक यूएस डॉलर के मुकाबले 17.82 रहा, वहीं 2024 में इसके कुछ मजबूत होकर 16.19 मिस्री पाउंड तक रहने की संभावना है। मुद्रा में यह मजबूती प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ने और मुद्रास्फीति में कमी की ओर संकेत करती है। घरेलू गैस उत्पादन बढ़ने के साथ ऊर्जा आयातों में भी कमी आएगी। इससे आयात बिल भी घटेगा और अंततः मिस्र गैस का निर्यात करने में भी सक्षम होगा। इससे व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। चालू खाता का मामूली घाटा 2020 में सरप्लस में तब्दील होने की संभावना है और 2020-24 के दौरान यह जीडीपी का 0.7% रह सकता है।

दक्षिण अफ्रीकी रैंड

दक्षिण अफ्रीका एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी रैंड यूएस डॉलर से से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। जबकि एक फलती-फूलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में जब निवेशों का प्रवाह विकसित देशों से उभरते बाजारों की ओर होता है तो डॉलर के साथ-साथ उभरती अर्थव्यवस्था की मुद्रा भी मजबूत होती है। किन्तु यूएस-चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध के चलते बढ़ी अनिश्चितताओं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेतों और अन्य के साथ-साथ ब्रेक्ज़िट के चलते दक्षिण अफ्रीकी रैंड भी अन्य उभरते हुए बाजारों की मुद्राओं के अनुरूप यूएस डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है।

पिछली तिमाही अर्थात जून-सितंबर 2019 तिमाही, के दौरान दक्षिण अफ्रीकी रैंड प्रति यूएस डॉलर 14.13 से 15.13 हो गया अर्थात इसमें 7.12% की गिरावट आई। हाल में यूएस डॉलर के मुकाबले दक्षिण अफ्रीकी रैंड में कुछ सुधार आया है और वर्तमान तिमाही के दौरान इसमें सुधार के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। मुद्रा की इस मूल्यवृद्धि से वैश्विक व्यापार से जुड़े विभिन्न मसलों और वार्ताओं का सकारात्मक समाधान हासिल करने में मदद मिल सकती है। ब्रेक्ज़िट डील की बढ़ी हुई संभावना और यूएस-चीन व्यापार डील के चलते दक्षिण अफ्रीकी रैंड में एक मूल्य पर स्थिरता आने से पहले और मजबूती आने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती से दक्षिण अफ्रीकी रैंड को यूएस डॉलर के मुकाबले और मजबूती मिल सकती है। हाल के कुछ समय में उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में मजबूती आई भी है।

ब्लूमबर्ग के अनुसार, आगामी दक्षिण अफ्रीका सीपीआई डाटा में सीपीआई के 4.30% (वर्ष-दर-वर्ष) रहने का पूर्वानुमान है, जो सेंट्रल बैंक के लक्ष्य के अनुसार, निचले बैंड में आता है। इसके अतिरिक्त, बजट भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा और इसका असर मुद्रा पर पड़ेगा।

स्विस फ्रैंक

स्विस फ्रैंक वर्तमान वर्ष के दौरान सबसे ज्यादा मूल्यवृद्धि दर्ज करने वाली/ बढ़ने वाली मुद्रा रही। इसका मूल्य प्रति यूरो 1.08 रहा और जून-सितंबर तिमाही के दौरान यह यूरो के मुकाबले पिछले दो वर्षों के उच्चतम स्तर पर रही। यूरो और अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले स्विस फ्रैंक में यह मजबूती कुछ हद तक ब्रेक्ज़िट की अनिश्चितता, यूरोपीय अर्थव्यवस्था में मंदी का रुख और व्यापार विवादों के चलते यूएस, जापान और स्विट्जरलैंड जैसी विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं से पूँजी के पलायन के कारण भी हो सकती है। स्विस फ्रैंक वर्ष की शुरुआत में यूरो के मुकाबले 1.1263 पर खुला और सितंबर तिमाही में 1.0842 पर बंद हुआ और इसमें 4% की वृद्धि दर्ज की गई ।

यूएस डॉलर से तुलना की जाए तो यूएस डॉलर के मुकाबले स्विस फ्रैंक 0.98 के स्तर पर खुला था और अप्रैल 2019 में यूएस डॉलर के मुकाबले स्विस फ्रैंक का मूल्य 1.02 रहा। इसके बाद सितंबर तिमाही में यह 0.99:1 प्रति यूएस डॉलर रहा।

तथापि, तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच कुछ सकारात्मक संकेतों के साथ, स्विस फ्रैंक में निकट भविष्य में गिरावट देखी जा सकती है। स्विस फ्रैंक के हालिया उतार-चढ़ाव को गौर से देखें तो पता चलता है कि इस स्तर के बाद इसमें बहुत सीमित मजबूती आई है और यूरो तथा अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं की तुलना में इसमें गिरावट की आशंका अधिक है। यही नहीं, तेजी से मूल्यवृद्धि दर्ज करने वाले स्विस फ्रैंक से देश के निर्यातों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है और मुद्रा को नियंत्रित रखने के लिए सेंट्रल बैंक को उपाय करने पड़ सकते हैं। तथापि, वर्तमान में ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है कि वर्तमान तिमाही में स्विस फ्रैंक में आई गिरावट के कारण सेंट्रल बैंक यह जरूरी न समझे। तथापि, मुद्रा में छेड़छाड़ को लेकर यूएस ट्रेजरी द्वारा की जा रही निगरानी के चलते इसकी संभावना कम ही है कि स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक स्विस फ्रैंक को कमजोर करने के लिए फॉरेक्स बाजार में कोई कदम उठाए।

कनाडाई डॉलर

वर्ष के दौरान, कनाडाई डॉलर अच्छी स्थिति में रहा और दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक रहा। वर्ष के प्रारंभ में यूएस डॉलर के मुकाबले कनाडाई डॉलर का मूल्य 1.36:1 यू एस डॉलर रहा और सितंबर तिमाही में यह 1.323:1 यू एस डॉलर रहा। इसमें लगभग 3% की गिरावट आई । इस बीच, जुलाई 2019 के दौरान यूएस डॉलर के मुकाबले कनाडाई डॉलर का मूल्य 1.30 के स्तर पर था।

दरअसल, दुनिया की अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कनाडाई अर्थव्यवस्था में मजबूती बने रहने के कारण कनाडाई डॉलर में भी मजबूती बनी रही। इससे कनाडा के सेंट्रल बैंक को मौद्रिक नीति के संबंध में किसी भी तरह का फैसला लेने में सुविधा हुई। यह इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी नीतिगत दरों को 1.75% पर अपरिवर्तित रखा, जबकि विभिन्न सेंट्रल बैंक अपने मौद्रिक नीति में उल्लेखनीय रूप से नरमी बरत रहे थे। इस अवधि के दौरान कनाडा में अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्चतर यील्ड अवसरों और बेहतर आर्थिक निष्पादन के चलते पूँजी आवक अच्छी रही। फलतः कनाडाई डॉलर भी मजबूत हुआ।

तथापि, वैश्विक मंदी से एकदम अप्रभावित रह जाना किसी भी देश के लिए कठिन होता है और अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के संकेत मिलने पर बैंक ऑफ कनाडा अन्य केंद्रीय बैंकों की भांति अपनी मौद्रिक नीति में नरमी बरत सकता है। हालांकि निकट भविष्य में इसकी संभावनाएं काफी कम दिखती हैं, किन्तु यदि ऐसा होता है तो बैंक ऑफ कनाडा को दरों में कटौती करनी होगी। लेकिन कनाडा की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि कनाडाई डॉलर आने वाले समय में थोड़ा और मजबूत होगा। भले ही यह मजबूती सीमित अवधि के लिए रहे, क्योंकि वर्ष के दौरान पहले ही इसका अधिमूल्यन हो चुका है।

वस्तु व्यापार

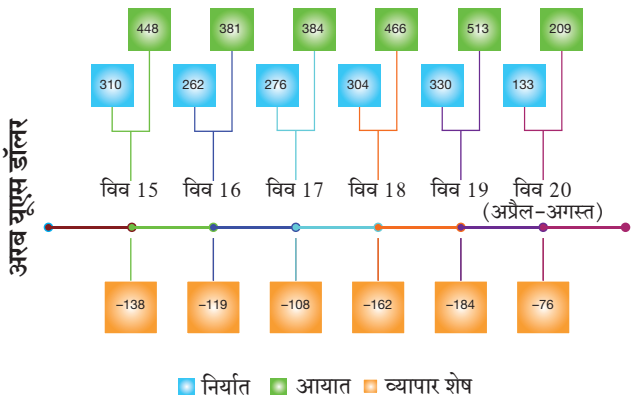

स्रोतः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सेवा व्यापार

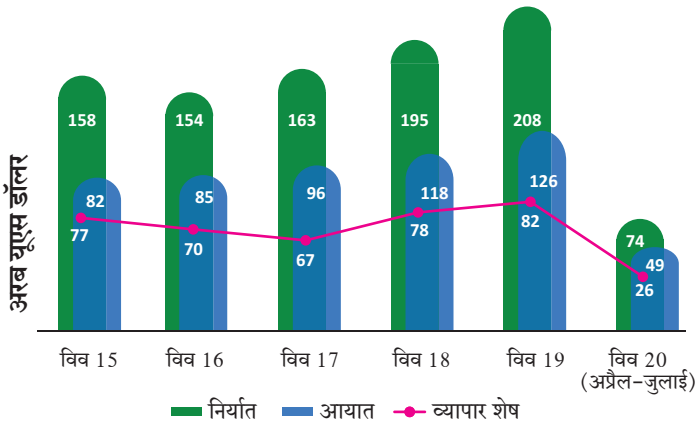

स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह

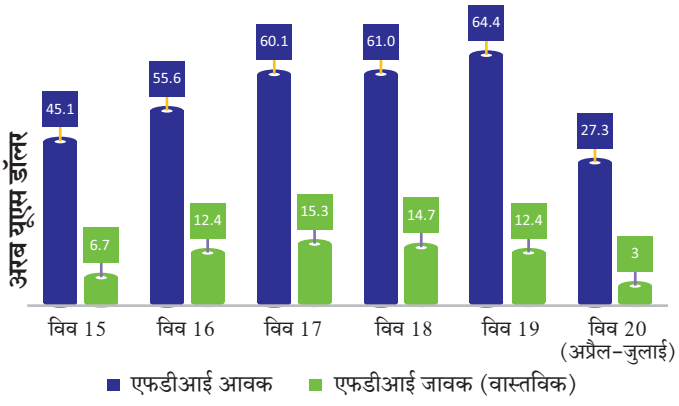

स्रोतः आरबीआई और वित्त मंत्रालय

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (%)

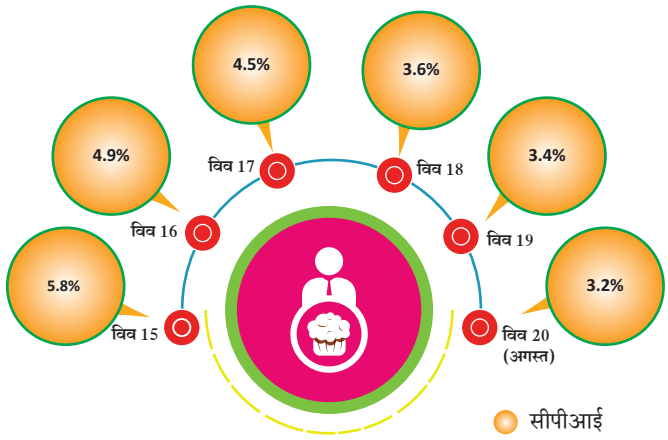

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चालू खाता घाटा

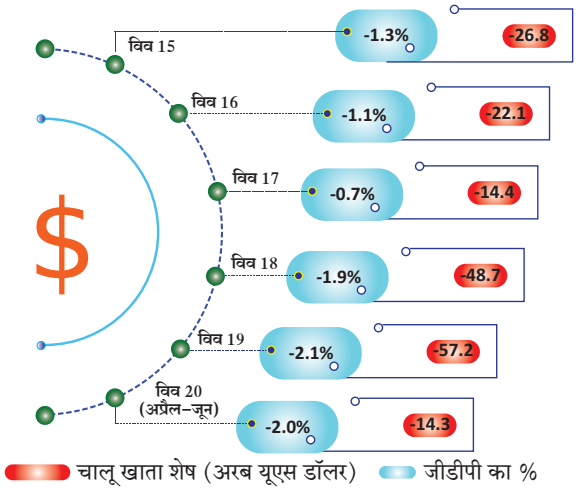

स्रोतः आरबीआई

सेक्टोरल उत्पादन

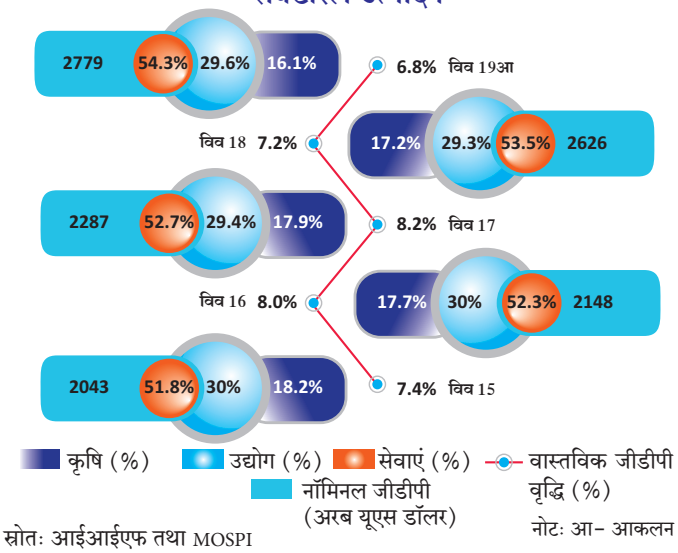

स्रोतः आईआईएफ तथा MOSPI

नोटः आ– आकलन

व्यापार और भागीदारी अवसर

व्यापार अवसर

जड़ी–बूटियां और बीज

तमिलनाडु के निर्यातक हैं, जो जड़ी–बूटियों, बीजों और केले की पत्तियों, काजू, सूरजमुखी के बीजों, जायफल, हल्दी, वेटिवर (खस–खस) तेल और जड़ों जैसे प्राकृतिक उत्पादों का कारोबार करते हैं।

तांबे की घंटियां

कच्छ के कुछ पारंपरिक दस्तकारों द्वारा तांबे की हस्तनिर्मित पारंपरिक घंटियों की बिक्री/निर्यात । घंटियां बनाने की यह पारंपरिक कला पिछले 200 वर्षों से चली आ रही है।

कलमकारी

आंध्र प्रदेश के एक निर्यातक हैं, जो कलमकारी में संलग्न हैं। कलमकारी सूती कपड़े पर हस्तचित्रित या ब्लॉक प्रिंट वाला शिल्प है। इसमें केवल प्राकृतिक रंग ही इस्तेमाल किए जाते हैं।

सवाई घास

सवाई घास, ग्रामीण महिलाओं द्वारा ओडिशा के जंगलों से इकट्ठी की जाती है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक फाइबर है। इस घास को सुखाकर रस्सियां, बक्से, ट्रे, टोकरियां आदि सजावटी सामान बनाए जाते हैं।

लकड़ी का सजावटी सामान

एक सामुदायिक संगठन, जो लकड़ी के सजावटी सामान बनाने वाले सूक्ष्म उद्यमों में लगे दस्तकारों और पारंपरिक शिल्पकारों / दस्तकार सोसायटियों में क्षमता विकास के जरिए उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।

इकत

यह कपड़े पर पैटर्न उकेरने की कला है, जो धागों पर उनकी बुनाई और रंगाई से पहले की जाती है। इकत एक–एक धागे को बुनकर तैयार किया जाता है, जिसमें धागे के बंडल के बंडल लग जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए: फोन: 2217 2600, एक्सटेंशन: 2822/2737, फैक्स: 2218 8268, ईमेल: mas@eximbankindia.in